

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई 2019—आषाढ़ 14, शक 1941

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2018

क्रमांक ई 1-01/2018/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री कुमार लाल चौहान, भा.प्र.से. (2009), आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ करता है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर से सहमति प्राप्त की गई.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2018

### शुद्धि पत्र

क्रमांक ई 1-01/2018/एक-2.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16-09-2018 द्वारा श्री कुमार लाल चौहान, भा.प्र.से. (2009) आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया गया है।

उक्त पदस्थापना में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 437/6/1/INST/ECI/FUNCT/MCC/2018, दिनांक 21-05-2018 में निर्धारित मानदण्ड को दृष्टिगत रखते हुए उनका पालन किया गया है।

अटल नगर रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2018

क्रमांक ई 1-01/2018/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से. (2005), संचालक, लोक शिक्षण तथा अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान, संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन को केवल मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान, तथा प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करता है। शेष प्रभार यथावत् रहेंगे।

2. श्री विनीत नंदनवार, भा.प्र.से. (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गरियाबंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मिशन संचालक, समग्र शिक्षा के पद पर पदस्थ करता है।

श्री विनीत नंदनवार, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मिशन संचालक, समग्र शिक्षा के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

3. सुश्री नुपूर राशि पन्ना, भा.प्र.से. (2015), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरायपाली, जिला-महासमुंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोण्डागांव के पद पर पदस्थ करता है।

4. श्री आर. के. खुंटे, संयुक्त आयुक्त, ठा. प्यारेलाल सिंह पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, निमोरा, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गरियाबंद के पद पर पदस्थ करता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर से सहमति प्राप्त की गई। उक्त पदस्थापना में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 437/6/1/INST/ECI/FUNCT/MCC/2018, दिनांक 21-05-2018 में निर्धारित मानदण्ड को दृष्टिगत रखते हुए उनका पालन किया गया है।

अटल नगर रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2018

क्रमांक ई 1-01/2018/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री आलोक अवस्थी, भा.प्र.से. (2002), प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, छ.ग. प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

2. श्री पी. सी. मिश्रा, भा.व.से. (1985), आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, छ.ग. रायपुर तथा अतिरिक्त प्रभार पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, छ.ग. रायपुर पदेन प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

3. श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, भा.व.से. (1987), सचिव, कृषि विभाग तथा गन्ना आयुक्त की सेवायें तत्काल प्रभाव से वन विभाग को लौटाई जाती हैं।

4. श्री जयसिंह म्हस्के, भा.व.से. (1988), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा./राज.), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अटल नगर की सेवायें वन विभाग से लेते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, वन विभाग के पद पर पदस्थ करता है।
5. श्री अमरनाथ प्रसाद, भा.व.से. (1998), मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अटल नगर की सेवायें वन विभाग से लेते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, कृषि विभाग के पद पर पदस्थ करता है।
6. श्री व्ही. के. छबलानी, दूरसंचार सेवा (1989), विशेष सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

अटल नगर रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2018

क्रमांक ई 1-01/2018/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री अलरमेलमंगई, डी., भा.प्र.से. (2004), विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा अति. प्रभार संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य खनिज विकास निगम को केवल विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करता है। शेष प्रभार यथावत् रहेंगे।

2. श्री संजय शुक्ला, भा.व.से. (1987), सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश एवं सदस्य सचिव, पर्यावरण संरक्षण मंडल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

3. श्री सुनील मिश्रा, भा.व.से. (1994), प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSIDC) की सेवायें सदस्य सचिव, पर्यावरण संरक्षण मंडल के पद पर पदस्थ करने हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग को सौंपता है।

4. श्री अरूण प्रसाद पी., भा.व.से. (2006), अतिरिक्त सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल तथा अतिरिक्त प्रभार उप सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSIDC) के पद पर पदस्थ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय सिंह, मुख्य सचिव.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 18 मई 2019

क्रमांक ई 1-09-2019/एफ-2.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14-05-2019 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2018 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों की पदस्थापना “Withdraw” किये जाने के संबंध में जारी आदेश राज्य शासन एतद्द्वारा निरस्त करता है। फलस्वरूप विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25-04-2019 यथावत् रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2018

क्रमांक ई 7-05/2005/एफ-2.—अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-19 के प्रावधान अनुसार श्रीमती शहला निगार, भा.प्र.से. को दिनांक 25-03-2018 से दिनांक 30-06-2018 तक स्वीकृत लघुकृत अवकाश में से दिनांक 30-04-2018 से दिनांक 30-06-2018 तक के अवकाश को मातृत्व अवकाश में परिवर्तित कर उक्त नियम-18 के प्रावधान अनुसार दिनांक 30-04-2018 से दिनांक 26-10-2019 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. उपरोक्त मातृत्व अवकाश की निरंतरता में अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-18(D) अनुसार दिनांक 27-10-2018 से दिनांक 11-01-2019 तक 77 दिवस का शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

### गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 6 जून 2019

क्रमांक एफ-1-06/2018/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से निम्नांकित भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों/राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री दीपक कुमार झा भापुसे-2007.	पुलिस अधीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू., रायपुर	पुलिस अधीक्षक जिला-बस्तर (जगदलपुर).
2.	श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल भापुसे-2008	सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, रायपुर	पुलिस अधीक्षक जिला-बिलासपुर.
3.	श्री दाउलूरी श्रवण भापुसे-2008	पुलिस अधीक्षक जिला-बस्तर (जगदलपुर)	सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, रायपुर.
4.	श्री सदानंद कुमार भापुसे-2010	पुलिस अधीक्षक जिला-सरगुजा (अंबिकापुर)	पुलिस अधीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू., रायपुर.
5.	श्री अभिषेक मीणा भापुसे-2010	पुलिस अधीक्षक जिला-बिलासपुर	सेनानी सी.टी.जे.डब्ल्यू. कॉलेज, कांकेर
6.	श्री आशुतोष सिंह भापुसे-2012	सेनानी प्रथम वाहिनी छसबल भिलाई	पुलिस अधीक्षक जिला-सरगुजा (अंबिकापुर)
7.	श्री शलभ कुमार सिन्हा भापुसे-2014	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुकमा (कैम्प कोटा)	पुलिस अधीक्षक, जिला-सुकमा

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	श्री दिव्यांग कुमार पटेल भापुसे-2014.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीजापुर.	पुलिस अधीक्षक, जिला-बीजापुर
9.	श्री गोवर्धन राम ठाकुर भापुसे	पुलिस अधीक्षक जिला-बीजापुर	सेनानी प्रथम वाहिनी छसबल, भिलाई
10.	श्री डी. एस. मरावी रापुसे	पुलिस अधीक्षक जिला-सुकमा	सेनानी, 21वीं वाहिनी छसबल (आई. आर.), करकाभाट, जिला बालोद.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

### आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 6 जून 2019

क्रमांक एफ-17-66/2018/25-2.—राज्य शासन एतद्वारा “प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)” योजनान्तर्गत भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पत्र क्रमांक 16015/08/2017 दिनांक 16-10-2018 द्वारा जारी मार्ग दर्शिका की कंडिका-15 के अधीन निम्नानुसार राज्य स्तरीय कार्यकारिणी एवं निगरानी समिति का पुनर्गठन करता है :—

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन  | अध्यक्ष    |
| 2. | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव छ.ग. शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/गृह विभाग/लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/अन्य संबंधित विभाग-वित्त विभाग/समाज कल्याण विभाग/आवास एवं पर्यावरण विभाग/श्रम विभाग/कृषि विभाग/खाद्य विभाग. | सदस्य      |
| 3. | प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत चिन्हित ग्रामों के संबंधित जिला प्रोग्राम डायरेक्टर (अधिकतम 5).   | सदस्य      |
| 4. | संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRDC) निमोरा, रायपुर.   | सदस्य      |
| 5. | दूरसंचार विभाग का प्रतिनिधि   | सदस्य      |
| 6. | अनुसूचित जाति कल्याण की दिशा में कार्य करने वाले दो विशेषज्ञ एवं दो सामाजिक कार्यकर्ता. (नामांकन पृथक से किया जावेगा).  | सदस्य      |
| 7. | राज्य लीड बैंक का प्रतिनिधि (SBI)   | सदस्य      |
| 8. | भारत सरकार ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि.   | सदस्य      |
| 9. | सचिव, छत्तीसगढ़ शासन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग.   | सदस्य-सचिव |
2. उक्त गठित समिति के निम्नानुसार कार्य होंगे.
1. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश प्रसारित करना. संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य/जिला/ब्लाक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर योजना को लागू करना एवं उसकी निगरानी करना.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 6 जून 2019

क्रमांक एफ-17-66/2018/25-2.—राज्य शासन एतद्वारा “प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)” योजनान्तर्गत भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पत्र क्रमांक 16015/08/2017 दिनांक 16-10-2018 द्वारा जारी मार्ग दर्शिका की कंडिका-14 के अधीन निम्नानुसार राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का पुनर्गठन करता है :—

- |     |   |            |
|-----|---|------------|
| 1.  | मान. मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग  | अध्यक्ष    |
| 2.  | मान. मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग   | उपाध्यक्ष  |
| 3.  | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव छ.ग. शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/गृह विभाग/लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/अन्य संबंधित विभाग-वित्त विभाग/समाज कल्याण विभाग/आवास एवं पर्यावरण विभाग/श्रम विभाग/कृषि विभाग/खाद्य विभाग. | सदस्य      |
| 4.  | संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRDC) निमोरा रायपुर   | सदस्य      |
| 5.  | छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिनिधि  | सदस्य      |
| 6.  | दूरसंचार विभाग का प्रतिनिधि   | सदस्य      |
| 7.  | अनुसूचित जाति कल्याण की दिशा में कार्य करने वाले विशेषज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता (कम से कम छः) (नामांकन पृथक से किया जावेगा).   | सदस्य      |
| 8.  | राज्य लीड बैंक का प्रतिनिधि (SBI)   | सदस्य      |
| 9.  | भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि.  | सदस्य      |
| 10. | सचिव, छत्तीसगढ़ शासन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग  | सदस्य सचिव |
2. उक्त गठित समिति के निम्नानुसार कार्य होंगे.
1. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश प्रसारित करना. संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य/जिला/ब्लाक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर योजना को लागू करना एवं उसकी निगरानी करना.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 6 जून 2019

क्रमांक एफ-17-66/2018/25-2.—राज्य शासन एतद्वारा “प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)” योजनान्तर्गत भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पत्र क्रमांक 16015/08/2017 दिनांक 16-10-2018 द्वारा जारी मार्ग दर्शिका की कंडिका-16 के अधीन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय, जिलास्तरीय एवं ग्राम स्तर पर कन्वरजेंस कमेटी का गठन करता है :—

(अ) **राज्य स्तरीय कन्वरजेन्स कमेटी :—**

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 1. | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग.   | अध्यक्ष |
| 2. | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव छ.ग. शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/गृह विभाग/लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/अन्य संबंधित विभाग-वित्त विभाग/समाज कल्याण विभाग/आवास एवं पर्यावरण विभाग/श्रम विभाग/कृषि विभाग/खाद्य विभाग. | सदस्य   |

3.	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत चिन्हित ग्रामों के संबंधित जिला प्रोग्राम डायरेक्टर.	सदस्य
4.	दूरसंचार विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRDC) निमोरा रायपुर.	सदस्य
6.	राज्य लीड बैंक का प्रतिनिधि (SBI)	सदस्य
7.	आयुक्त/संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	सदस्य सचिव

(ब) **जिला स्तरीय कन्वरजेन्स कमेटी :—**

1.	जिला दण्डाधिकारी/कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	निम्नांकित विभागों/संगठनों के जिला प्रमुख/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/खाद्य विभाग/ऊर्जा विभाग/कृषि विभाग/विद्युत वितरण कंपनी (डिस्काम)/इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/अन्य संबंधित विभाग-वित्त विभाग/समाज कल्याण विभाग/आवास एवं पर्यावरण विभाग/श्रम विभाग/कृषि विभाग/खाद्य विभाग.	सदस्य
3.	संबंधित ग्राम के विलेज प्रोग्राम डायरेक्टर	सदस्य
4.	दूरसंचार/बीएसएनएल का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRDC) निमोरा रायपुर के प्रतिनिधि.	सदस्य
6.	जिला लीड बैंक का प्रतिनिधि (SBI)	सदस्य
7.	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास	सदस्य सचिव

(स) **ग्राम स्तरीय कन्वरजेन्स कमेटी :—**

1.	सरपंच ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2.	ग्राम पंचायत के सभी अनुसूचित जाति के सदस्य	सदस्य
3.	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम, आदि	सदस्य
4.	लोक निर्माण विभाग एवं पंचायत विभाग के कर्मचारी/अधिकारी	सदस्य
5.	मनरेगा के फील्ड वर्कर	सदस्य
6.	स्कूल शिक्षक	सदस्य
7.	संबंधित अन्य विभागों के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	विलेज डेवलपमेंट आफिसर	सदस्य
9.	संचालक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRDC) निमोरा रायपुर के प्रतिनिधि.	विशेष आमंत्रित सदस्य
10.	ग्राम पंचायत का एक अनुसूचित जाति का सदस्य	सदस्य सचिव

2. उक्त गठित समितियों के निम्नानुसार कार्य होंगे.

1. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रसारित दिशा-निर्देश अनुसार कनवरजेन्स की कार्यवाही सुनिश्चित करना. संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य/जिला/ब्लाक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर योजना को लागू करना एवं उसकी निगरानी करना.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

**वित्त विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर**

नया रायपुर, दिनांक 19 जून 2018

क्रमांक 765/एफ 04-03954/2017/स्था.—छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा/अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिक्रमित करते हुये, राज्य शासन एतद्वारा राज्य वित्त सेवा एवं अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**प्रेमा गुलाब एक्का, अवर सचिव.**

परिशिष्ट "अ"

**छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा/अधीनस्थ लेखा सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम**

क्र. (1)	प्रशिक्षण का नाम/विषय (2)	प्रशिक्षण अवधि (3)	प्रशिक्षण स्थल (4)	रिमार्क (5)
1.	संचालनालय के कार्य एवं गतिविधियों का प्रशिक्षण.	02 सप्ताह	संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन	
2.	विभिन्न विभागीय गतिविधियों का प्रशिक्षण	04 सप्ताह	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी	वित्त विभाग सहित चिंहांकित विभागाध्यक्ष कार्यालय. 1. आयुक्त लोक शिक्षण 2. आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग 3. विकास आयुक्त 4. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 5. कृषि विश्वविद्यालय 6. मार्कफेड 7. निर्वाचन कार्यालय 8. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम 9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक 10. प्रमुख अभियंता लोक निर्माण 11. आयुक्त वाणिज्यिक कर 12. आयुक्त परिवहन 13. महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक 14. आयुक्त आबकारी 15. आयुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा के संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा.
3.	शासकीय नियमों का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण.	04 सप्ताह	शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर.	संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा निर्धारित तिथि पर आयोजित होगा.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	शासकीय लेखांकन एवं अंकेक्षण संबंधी प्रशिक्षण.	02 सप्ताह	छत्तीसगढ़ महालेखाकार	संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा निर्धारित तिथि पर आयोजित होगा.
5.	लोक लेखा समिति	01 सप्ताह	छत्तीसगढ़ विधानसभा	संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा निर्धारित तिथि पर आयोजित होगा.
6.	रिजर्व बैंक की कार्य प्रणाली	01 सप्ताह	भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर	संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा निर्धारित तिथि पर आयोजित होगा.
7.	आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	06 सप्ताह	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा निर्धारित तिथि पर आयोजित होगा.
कुल 20 सप्ताह				

### वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 29 मई 2019

क्रमांक/एफ 01-03/2017/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित निम्नलिखित वर्ष 2017 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को 04 माह के क्षेत्रीय प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए नवीन पदस्थापना पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वृत्त का नाम (3)	वनमण्डल का नाम (4)
1.	श्री अभिषेक जोगावत	सरगुजा	बलरामपुर
2.	श्री आयुष जैन	बिलासपुर	कोरबा
3.	श्री जाधव सागर रामचन्द्रा	जगदलपुर	जगदलपुर
4.	श्री शशिगानन्दन के	रायपुर	धमतरी
5.	श्री सौरभ सिंह ठाकुर	दुर्ग	राजनांदगांव
6.	श्री वरूण जैन	रायपुर	बलौदाबाजार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजय कुमार चौधरी, अवर सचिव.

**राजस्व विभाग**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 18 जून 2019

प्रारूप-एक  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/10394/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	हराभाठा	1.463 हे.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 10-07-2019 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन सुक्लाखार पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	18 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	18 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 5607.66 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 1991 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 18 जून 2019

**प्रारूप-एक**  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/10396/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	मोंगरा	4.705 हे.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 15-07-19 को समय 12.00 बजे से स्थान सामुदायिक भवन मोंगरा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	53 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	53 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 5607.66 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 1991 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 18 जून 2019

**प्रारूप-एक**  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/10398/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	रोहिना	0.852 हे.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 22-07-2019 को समय 12.00 बजे से स्थान सामुदायिक भवन रोहिना पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	15 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	15 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 5607.66 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 1991 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 18 जून 2019

**प्रारूप-एक**  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/10400/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	रंगबेल	3.179 हे.	गंगदेई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 03-07-19 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन रंगबेल पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	गंगदेई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	33 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	33 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 590.25 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 265 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 18 जून 2019

**प्रारूप-एक**  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/10402/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	मड़वाढोढ़ा	2.181 हे.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 19-07-2019 को समय 12.00 बजे से स्थान सामुदायिक भवन मड़वाढोढ़ा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	33 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	33 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 5607.66 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 1991 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 18 जून 2019

**प्रारूप-एक**  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/10404/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	सरईसिंगार	0.173 हे.	गंगदेई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 06-07-2019 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन रंगबेल पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	गंगदेई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	06 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	06 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 590.25 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 265 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 18 जून 2019

**प्रारूप-एक**  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/10406/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	कसरैगा	1.737 हे.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 26-06-19 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन ढपढप पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	19 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	19 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 5607.66 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 1991 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.



कोरबा, दिनांक 18 जून 2019

**प्रारूप-एक**  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/10408/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	भेजीनारा	4.021 हे.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 12-07-2019 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन अरदा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	29 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	29 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 5607.66 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 1991 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 18 जून 2019

**प्रारूप-एक**  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/10410/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	ढपढप	2.750 हे.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 26-06-19 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन ढपढप पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	42 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	42 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 5607.66 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 1991 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 18 जून 2019

**प्रारूप-एक**  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/10412/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	भाटीकुड़ा	0.169 हे.	तेन्दुवाही व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 29-06-19 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन गंगदेई पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	तेन्दुवाही व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	03 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	03 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 538.74 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 192 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 18 जून 2019

**प्रारूप-एक**  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/10416/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कोरबा	कोड़ियाघाट	111.469 हे.	औद्योगिक प्रयोजन (राखड़ बांध निर्माण)

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 11-07-2019 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम कोड़ियाघाट नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	औद्योगिक प्रयोजन (राखड़ बांध निर्माण)
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	829
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	225
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	50
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	445 करोड़
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	2600 मेगावाट बिजली उत्पादन का राख संग्रहण
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 18 जून 2019

**प्रारूप-एक**  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/10419/भू-अर्जन/2019.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	पुरैना	2.482 हे.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 17-07-2019 को समय 12.00 बजे से स्थान सामुदायिक भवन पुरैना पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	32 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	32 परिवार
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 5607.66 लाख
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	परियोजना से 1991 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**किरण कौशल**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

कांकेर, दिनांक 10 जून 2019

क्रमांक/01/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	दुर्गुकोंदल	भूस्की प.ह.नं. 10	0.40	पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर.	बीएसएफ कैम्प की सुरक्षा हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**के. एल. चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.**

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व  
एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

महासमुंद, दिनांक 29 मई 2019

क्रमांक 206/भू-अर्जन/22 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	साल्हेभाठा प.ह.नं. 48	2.00	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 29 मई 2019

क्रमांक 207/भू-अर्जन/14 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	खेमड़ा प.ह.नं. 30	1.77	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 29 मई 2019

क्रमांक 208/भू-अर्जन/18 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	सिमगांव प.ह.नं. 49	0.11	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 29 मई 2019

क्रमांक 209/भू-अर्जन/19 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	डोंगरगांव प.ह.नं. 30	0.17	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 29 मई 2019

क्रमांक 210/भू-अर्जन/13 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	छिबरा प.ह.नं. 49	0.75	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.



महासमुंद, दिनांक 29 मई 2019

क्रमांक 211/भू-अर्जन/21 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	बैगाखम्हरिया प.ह.नं. 48	1.48	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत माईनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 29 मई 2019

क्रमांक 212/भू-अर्जन/23 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	कस्तुरबोड़ प.ह.नं. 6	0.27	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	गबौद जलाशय योजना के अंतर्गत डुबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 29 मई 2019

क्रमांक 213/भू-अर्जन/17 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	बागबाहरा	सेनभाठा प.ह.नं. 31	1.00	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दरबेकेरा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत पाईप लाईन एवं मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छत्तीसगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**सुनील कुमार जैन**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़  
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व  
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर  
(1)  
रकबा  
(हेक्टेयर में)  
(2)

सूरजपुर, दिनांक 31 मई 2019

क्रमांक/3601/01/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-सूरजपुर

(ख) तहसील-प्रतापपुर

(ग) नगर/ग्राम-गौरा, प.ह.नं. 32

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.01 हेक्टेयर

582	0.50
583/1	0.15
584	0.12
745	0.14
754	0.08
755	0.04
739/3	0.04
739/2	0.05
739/1	0.02
738	0.02
761/4	0.06
761/3	0.06
761/1	0.06
762	0.21
752/2	0.14

(1)	(2)	(1)	(2)
752/3	0.32	1115	0.04
		1113	0.03
योग	16	830/1	0.02
		930/4	0.01
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोटेया व्यपवर्तन सिंचाई योजना के नहर हेतु.		930/5	0.03
		890/3	0.08
		930/3	0.03
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), प्रतापपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.		934	0.01
		844	0.01
		935	0.01
		936	0.01
		944	0.07
सूरजपुर, दिनांक 31 मई 2019		945/1	0.02
		945/2	0.02
क्रमांक/3603/01/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		924	0.02
		923/1	0.02
		922	0.02
		921	0.04
		899	0.03
		1557	0.03
		900	0.03
		401	0.03
		845	0.05
		837	0.03
		838	0.01
		834	0.04
(1) भूमि का वर्णन-		833	0.06
(क) जिला-सूरजपुर		831	0.04
(ख) तहसील-प्रतापपुर		829	0.06
(ग) नगर/ग्राम-कोटेया, प.ह.नं. 32		1454	0.05
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.99 हेक्टेयर		1508/1	0.06
खसरा नम्बर	रकबा	1503	0.01
	(हेक्टेयर में)	1505	0.01
(1)	(2)	1490	0.05
		1489	0.03
608	0.03	1558	0.03
583	0.01	1559/1	0.04
605	0.05	1508/3	0.05
602/2	0.03	846	0.02
602/3	0.14	योग	52
1153	0.16		1.99
1106	0.16	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोटेया व्यपवर्तन सिंचाई योजना हेतु.	
1107	0.04	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), प्रतापपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
1453/1	0.02	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
1453/2	0.02	दीपक सोनी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	
1108/2	0.04		
1109	0.02		
1110	0.02		

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड  
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जून 2019

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/1703.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.सा.अधि./2017-18/3976 दिनांक 26-08-2017 द्वारा श्री कैलाश वर्मा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दुर्ग को कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग जिला दुर्ग का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

कलेक्टर, जिला दुर्ग (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/मण्डी/स्था./भा.सा.अ.नि./2018-19/1211 दुर्ग दिनांक 18-03-2019 द्वारा श्री कैलाश वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दुर्ग के स्थानांतरण होने के कारण उनके स्थान पर श्री जी. एस. धुर्वे, उप संचालक कृषि दुर्ग को कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग के भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री कैलाश वर्मा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दुर्ग के स्थान पर श्री जी. एस. धुर्वे उपसंचालक कृषि दुर्ग को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग जिला दुर्ग का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

अभिनव अग्रवाल,  
प्रबंध संचालक.

## कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

दन्तेवाड़ा, दिनांक 1 जून 2019

क्रमांक 346/भू.अ./2019.—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम एवं असर्वेक्षित ग्रामों को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कालम (2) में दर्शित असर्वेक्षित वन ग्राम इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा अर्थात् :—

क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हे. में)	वन ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बट्टीनामा	222.595	उत्तर-वन ग्राम पुरनतराई दक्षिण-वन ग्राम जोड़ातराई पूर्व-आरक्षित वन पश्चिम-वन ग्राम नागफनी	11	घोठपाल	गीदम	दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	भालूनाला	572.016	उत्तर-आरक्षित वन दक्षिण-आरक्षित वन/वन ग्राम बट्टीनामा. पूर्व-आरक्षित वन पश्चिम-राजस्व ग्राम हिड़पाल	12	हिड़पाल	गीदम	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
3.	बालेंगपाल	317.485	उत्तर-आरक्षित वन दक्षिण-राजस्व ग्राम हिड़पाल पूर्व-आरक्षित वन पश्चिम-संरक्षित वन/राजस्व ग्राम उपेट.	12	हिड़पाल	गीदम	—,,—
4.	मल्लूमुण्डा	98.081	उत्तर-आरक्षित वन दक्षिण-आरक्षित वन/अलीबहार नाला/ राजस्व ग्राम कोरलापाल. पूर्व-आरक्षित वन पश्चिम-आरक्षित वन/इंद्रावती नदी	02	मुचनार	गीदम	—,,—

No. 346/L.R./2019.—Whereas, the forest and unsurveyed villages shown in schedule below have been provided the recognition of Forest rights relating to modification as revenue village by the forest Rights Committee South Bastar Dantewada under the provision of clause (h) of sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (no. 02 of 2007).

And whereas as per the Revenue Departments Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned:

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959), it is hereby, Declare that unsurveyed forest village shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the dated of this notification, namely :—

S. No.	Name of Forest Village	Total Area of Village (in hect.)	Boundaries of Forest Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Battinama	222.595	North-Forest Village Purantarai South-Forest Village Jodatarai East-Reserve Forest West-Forest Village Nagfani	11	Ghotpal	Geedam	South Bastar Dantewada
2.	Bhalunala	572.016	North-Reserve Forest South-Reserve Forest Village-Battinama. East-Reserve forest West-Revenue Village Hidpal	12	Hidpal	Geedam	—,,—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Balengpal	317.485	North-Reserve Forest South-Revenue Village Hidpal East-Reserve Forest West-Protected Forest/Revenue Village Upet.	12	Hidpal	Geedam	South Bastar Dantewada
4.	Mallumunda	98.081	North-Reserve Forest South-Reserve Forest Alibahar Nala/Revenue Village- Korlapal. East-Revenue forest West-Reserve Forest/Indravati Rever.	02	Muchnar	Geedam	—,—

टोपेश्वर वर्मा,  
कलेक्टर.

### उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 9th April 2019

No. 446/Confdl./2019/II-3-14/2000 (Pt.-III).—On the application of Ku. Bhawana Nayak, Member of Lower Judicial Service, presently posted as Secretary, District Legal Services Authority, Baikunthpur, she is hereby, permitted to change her name as “Smt. Bhawana Nayak Thakur” in place of “Ku. Bhawana Nayak” and to incorporate the name of her husband “Shri Devashish Thakur” in place of her father’s name “Shri Radheshyam Nayak” in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

Bilaspur, the 11th April 2019

No. 460/Confdl./2019/II-3-14/2000.—On the basis of the application of Shri Manoj Kumar Prajapati, Member of Higher Judicial Service, presently posted as I Additional District & Sessions Judge, Mahasamund alongwith the documentary evidence attached by him, he is hereby, permitted to prefix the title “Dr.” before his name. It is directed that in all his records, his name be changed as “Dr. Manoj Kumar Prajapati” in place of “Manoj Kumar Prajapati”.

Bilaspur, the 11th April 2019

No. 462/Confdl./2019/I-8-2/2010.—The following Senior Civil Judge, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in Column No. (4) having jurisdiction of the District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date she assumes charge of her office :—

TABLE

S. No.	Name & presently posted as	From	To	Jurisdiction of the Court	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Smt. Yashoda Nag, Civil Judge Class-I.	Gunderdehi	Durg	Durg, Balod and Bemetara District.	Labour Judge, Labour Court.

Bilaspur, the 11th April 2019

No. 464/Confdl./2019/II-3-1/2019.—The temporary posting of Shri Pankaj Dixit as Civil Judge Class-I, Gunderdehi made vide Registry Order No. 1277/Confdl./2018/II-3-1/2018 dated 06-12-2018, is hereby, regularized and he is posted as Civil Judge Class-I, Gunderdehi on regular basis w.e.f. 22-04-2019.

Bilaspur, the 11th April 2019

No. 466/Confdl./2019/II-3-1/2019.—The following Members of Lower Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, who are posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) are, now, posted in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Presently posted in the capacity (3)	Henceforth posted in the capacity (4)
1.	Ku. Tanu Shree Gavel	Civil Judge Class-II, Kharsiya	I Civil Judge Class-II, Kharsiya
2.	Ku. Jasvinder Kaur Ajmani	Civil Judge Class-II, Kharsiya	II Civil Judge Class-II, Kharsiya

**Note :—** The Court of Civil Judge Class-II, Kharsiya shall henceforth be addressed as the Court of I Civil Judge Class-II, Kharsiya.

By order of the High Court,  
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2019

क्रमांक 81/दो-2-10/2007.—श्री के. विनोद कुजूर, तत्कालीन न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कबीरधाम (कवर्धा), वर्तमान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 06-03-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2019

क्रमांक 82/दो-2-10/2007.—श्री के. विनोद कुजूर, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 06-03-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,  
एम. पी. बिसोई, बजट अधिकारी.